

सिविल विविध

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन के समक्ष ।

राम चंद, ----- याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, ----- उत्तरदाता।

सिविल याचिका संख्या 1470 सन 1965

27 नवंबर, 1969

पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम (1963 का X) - धारा 24 - पंजाब किरायेदारी अधिनियम (1887 का XVI) - धारा 82, 85 और 88 – सिविल प्रक्रिया संहिता (Vसन 1908) आदेश 47 नियम 1 - कानून की वर्तमान व्याख्या के आधार पर कलेक्टर का आदेश - कानून की व्याख्या में परिवर्तन पर आदेश की समीक्षा - क्या अनुमेय है - राजस्व अधिकारियों की समीक्षा की शक्ति - क्या संहिता के आदेश 47 नियम 1 के आधार पर ही इसका प्रयोग होना चाहिए ।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 24 के तहत समीक्षा की शक्तियां पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धारा 82 के तहत समान हैं। सभी ग्रेड के सभी राजस्व अधिकारियों के पास अपने स्वयं के आदेशों और उनके पूर्ववर्तियों के आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियां हैं, बशर्ते कि उन आदेशों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई हो। किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत राजस्व अधिकारी में निहित समीक्षा की शक्ति असीमित नहीं है और इसका उपयोग किसी भी समय और किसी भी मामले में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे भ्रामक परिणाम होंगे और राजस्व अधिकारियों को शक्तियां प्रदान होंगी जिनका मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया जा सकता है और अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा। इस शक्ति का प्रयोग उन मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाएगा जो आमतौर पर न्यायालयों पर लागू होते रहे हैं। किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत समीक्षा की अपरिभाषित शक्ति का उपयोग कलेक्टर द्वारा अपने पहले के आदेश को बदलने और बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो उस समय मौजूद कानून की व्याख्या के अनुसार पारित किया गया था, इस आधार पर कि बाद में कानून की व्याख्या में बदलाव हुआ है। केवल यह तथ्य कि पहले के आदेश के पारित होने के बाद कानून की एक अलग व्याख्या हुई है, कलेक्टर को अपने पिछले आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। (पैरा 3 और 4)।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 85 के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस प्रकार यह मानने का कोई आधार नहीं होगा कि राजस्व अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में निर्दिष्ट आधारों पर समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना है। (पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 के आदेश दिनांकित 29 मार्च, 1965, 5 फरवरी, 1964 और 21 सितम्बर, 1962 को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

आर.एन. मित्तल, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

डी.एस. तेवतिया, महाधिवक्ता, (हरियाणा), उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति पी.सी. जैन - राम चंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें कलेक्टर, आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के क्रमशः 21 सितंबर, 1962, 5 फरवरी, 1964 और 29 मार्च, 1965 के आदेशों को रद्द करते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने कि प्रार्थना कि है।

- 2) जिन संक्षिप्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है, वे यह हैं कि याचिकाकर्ता के पास 101.65 साधारण एकड़ 31.59 मानक एकड़ भूमि थी और कलेक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 ने 10 जून, 1961 के अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 96.56 साधारण एकड़/30 मानक एकड़ को अपने अनुमेय क्षेत्र के रूप में रखने की अनुमति दी थी और शेष क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया था। दिनांक 10 जून, 1961 का आदेश कलेक्टर द्वारा *माहिया* और *अन्य* बनाम *दलीप* और *अन्य*¹ मामले में वित्तीय आयुक्त के निर्णय के बाद पारित किया गया था। हालांकि, *माहिया* के मामले में निर्णय, (1), एक अच्छा कानून नहीं रहा और अब स्थापित कानून यह है कि एक गैर-विस्थापित व्यक्ति अपने अनुमेय क्षेत्र के रूप में 30 मानक एकड़ का हकदार होगा, लेकिन यदि ये 30 मानक एकड़ साधारण एकड़ में परिवर्तित होने पर, 60 एकड़ से अधिक हो जाते हैं, तो वह केवल 60 एकड़ का हकदार होगा। कानून की बदली हुई व्याख्या को देखते हुए, कलेक्टर ने मामले को फिर से खोला और आक्षेपित आदेश द्वारा, 10 जून, 1961 के अपने पिछले आदेश की समीक्षा की और याचिकाकर्ता को केवल 60 साधारण एकड़ रखने की अनुमति दी और शेष क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया।
- 3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया कि मुख्य आधार यह था कि मामले की परिस्थितियों में कलेक्टर के पास 10 जून, 1961 के अपने पिछले आदेश की समीक्षा करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार, समीक्षा के लिए कोई वैध आधार मौजूद नहीं था और केवल इस तथ्य के लिए कि पहले के आदेश के पारित होने के बाद कानून की एक अलग व्याख्या हुई थी, कलेक्टर को अपने पिछले आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया था कि कलेक्टर द्वारा लगभग 15 महीने की अवधि के बाद समीक्षा की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कलेक्टर के पास समीक्षा की असीमित शक्ति है और इसे बिना किसी सीमा के कानूनी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। महाधिवक्ता के अनुसार, राजस्व अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली समीक्षा की शक्ति पर कानून द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या इस मामले की परिस्थितियों में, कलेक्टर के पास 10 जून, 1961 के अपने पिछले आदेश की समीक्षा करने का कोई क्षेत्राधिकार था।

¹ 1961 एल.एल.टी. 11

- 4) पूरे मामले और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर अपना विचारशील विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क में काफी बल है, और ऊपर उल्लिखित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए। कानून के प्रासंगिक प्रावधान जिनके साथ हम संबंधित हैं, वे पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 24 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धारा 82 (इसके बाद 'किरायेदारी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) हैं, जो निम्नानुसार हैं: —

“24. अपील, समीक्षा और संशोधन।

इस अधिनियम के तहत अपील, समीक्षा और संशोधन के संबंध में प्रावधान, जहां तक हो सके, वही होगा जो पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम XVI) की धारा 80, 81, 82, 83 और 84 में प्रदान किया गया है।

“82. राजस्व अधिकारियों द्वारा समीक्षा।

1. एक राजस्व अधिकारी, इस प्रकार, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या इच्छुक किसी भी पक्ष के आवेदन पर, समीक्षा कर सकता है, और इस तरह समीक्षा कर सकता है, स्वयं या कार्यालय में अपने पूर्ववर्तियों में से किसी द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित, उलट या पुष्टि कर सकता है:

निम्नानुसार प्रदान किया गया है: —

- a. जब कोई आयुक्त या कलेक्टर किसी ऐसे आदेश की समीक्षा करना आवश्यक समझता है जिसे उसने स्वयं पारित नहीं किया है और जब कलेक्टर से नीचे के वर्ग का राजस्व अधिकारी किसी आदेश की समीक्षा करने का प्रस्ताव करता है, चाहे वह स्वयं या कार्यालय में अपने पूर्ववर्तियों में से किसी के द्वारा पारित किया गया हो, तो वह पहले राजस्व अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करेगा, जिसके नियंत्रण के अधीन वह तुरंत है;
 - b. किसी आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह आदेश पारित होने के नब्बे दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, या जब तक कि आवेदक राजस्व अधिकारी को संतुष्ट नहीं करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने का पर्याप्त कारण था;
 - c. एक आदेश को संशोधित या उलट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रभावित पक्षों को उचित नोटिस नहीं दिया गया है, जिससे आदेश के समर्थन में उपस्थित होने और सुने जाने के लिए;
 - d. एक आदेश जिसके खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई है, उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी।
2. इस धारा के प्रयोजन के लिए कलेक्टर को निम्न वर्ग के किसी भी राजस्व अधिकारी के कार्यालय में उत्तराधिकारी माना जाएगा, जिसने जिला छोड़ दिया है या राजस्व अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया है, और जिसके लिए कार्यालय में कोई उत्तराधिकारी नहीं है।
 3. अपील उस आदेश से नहीं की जाएगी जो पिछले आदेश की समीक्षा करने या उसकी पुष्टि करने से इनकार करता हो।

अधिनियम की धारा 24 के तहत समीक्षा की शक्तियां किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत समान हैं। किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि सभी ग्रेड के सभी राजस्व अधिकारियों के पास अपने स्वयं के आदेशों और उनके पूर्ववर्तियों के आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियां हैं, बशर्ते कि उन आदेशों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई हो। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि धारा 82 में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47, नियम 1 में दिए गए किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। एकमात्र सुरक्षा उन मामलों में प्रदान की जाती है, जहां पूर्ववर्ती-इन-ऑफिस के आदेश की समीक्षा की जानी है। इस प्रकार, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि समीक्षा की असीमित शक्तियां राजस्व अधिकारियों में निहित हैं। इस प्रश्न का उत्तर स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मित्तल के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि समीक्षा की शक्ति का उपयोग राजस्व अधिकारियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 और आदेश 47, नियम 1 में निर्धारित आधारों के अनुसार किया जाना चाहिए। किरायेदारी अधिनियम की धारा 88 राजस्व न्यायालयों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है, न कि राजस्व अधिकारियों के लिए। माना जाता है कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 85 के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, यह मानने का कोई आधार नहीं होगा कि राजस्व अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में निर्दिष्ट आधारों पर समीक्षा की शक्ति का उपयोग करना है। तथापि, मैं विद्वान महाधिवक्ता के इस तर्क से सहमत होने के लिए स्वयं को राजी नहीं कर पाया हूँ कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी में निहित समीक्षा की शक्ति असीमित है और इसका प्रयोग किसी भी समय और किसी भी मामले में किया जा सकता है क्योंकि इससे भ्रामक परिणाम होंगे व अनिश्चितता का माहौल बनेगा और राजस्व अधिकारियों को ऐसी शक्तियां प्रदान होंगी जिनका दुरुपयोग या मनमाने ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधायिका कभी भी राजस्व अधिकारियों को कानून के सामान्य न्यायालयों की तुलना में समीक्षा की व्यापक शक्तियां प्रदान करने का इरादा नहीं कर सकती है। मेरे विचार से, किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के साथ अधिनियम की धारा 24 के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, जो उन मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होगा जो आम तौर पर न्यायालयों पर लागू होते हैं। कुछ इसी तरह का सवाल हरनेक सिंह बनाम आयुक्त, जुलुंदूर मंडल और अन्य² में भी उठा, जिसमें न्यायमूर्ति आर एस नरूला ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था -

"12. श्री मोंगिया ने यह दिखाने के लिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाना है, पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, धारा 88 राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित है, न कि राजस्व अधिकारियों से। धारा 85 राज्य सरकार को पंजाब किरायेदारी अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। यह स्वीकृत है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 82 के तहत समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग से संबंधित कोई नियम धारा 85 के तहत तैयार नहीं किया गया है। किसी भी नियम और किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए सामान्य सिद्धांतों को राजस्व अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए कार्यवाही पर लागू करना होगा। ये सिद्धांत सर्वविदित हैं और यदि इस मामले को उनके समक्ष पुन उठाया जाता है तो इस मामले से निपटते समय उपयुक्त राजस्व अधिकारियों को इन्हें ध्यान में रखना

होगा। इस विशेष मामले में, ऐसा लगता है कि विद्वान आयुक्त ने मामले के इस पहलू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संभवतः कुछ स्थापित प्रथाओं के कारण, उनका विचार था कि इन सभी आपत्तियों को राजस्व अधिकारी द्वारा तय किया जाना है, न कि मंजूरी देने वाले अधिकारी द्वारा।”

- 5) अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस आधार पर किया गया था कि माहिया(1) के मामले में वित्तीय आयुक्त के फैसले के बाद कानून की एक अलग व्याख्या की गई थी। मेरे विचार से यह किसी भी मामले में समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत समीक्षा की अपरिभाषित शक्ति का उपयोग कलेक्टर द्वारा अपने पहले के आदेश को बदलने और बदलने के लिए नहीं किया जा सकता था, जो उस समय मौजूद कानून की व्याख्या के अनुसार पारित किया गया था, इस आधार पर कि बाद में कानून की व्याख्या में बदलाव हुआ है। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि कलेक्टर का पिछला आदेश कानून के गलत दृष्टिकोण पर पारित किया गया था, लेकिन, जैसा कि पहले कहा गया था, यह अपने आप में समीक्षा का कोई आधार नहीं है। इसी तरह का सवाल बड़ी संख्या में उन मामलों में भी उठा जहां एक भूस्वामी के अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करते समय बंजार कदीम और बंजार जदीद भूमि को ध्यान में रखा गया था। नेमी चंद जैन बनाम वित्तीय आयुक्त, पंजाब और अन्य³ के मामले में इस अदालत के फैसले के बाद, यह निर्णीत किया गया था कि ऐसी भूमि, 'भूमि' की परिभाषा में नहीं आती है, भूमि मालिकों द्वारा समीक्षा के लिए कलेक्टर के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए थे; लेकिन उन सभी आवेदनों को इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया गया था कि समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस आधार पर अनुमति नहीं थी कि कानून पर एक अलग व्याख्या रखी गई थी। इस संबंध में अमर सरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य⁴ में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को देखें। वर्तमान याचिका में भी बिल्कुल यही स्थिति है। यदि कोई निजी व्यक्ति कानून की बदली हुई व्याख्या के आधार पर कलेक्टर द्वारा किसी आदेश की समीक्षा की मांग नहीं कर सकता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक राजस्व अधिकारी उस आधार पर अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा कैसे कर सकता है। जिस आधार पर विद्वान कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई है, - उनके दिनांक 21 सितंबर, 1962 के आदेश के माध्यम से, पिछले आदेश की समीक्षा करने के लिए एक वैध और कानूनी आधार नहीं है और इस प्रकार कलेक्टर के 21 सितंबर, 1962 के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के आदेश भी स्वतः खारिज हो जाएंगे।
- 6) विद्वान वकील की दूसरी दलील कि किरायेदारी अधिनियम की धारा 82 के तहत एक राजस्व अधिकारी किसी भी समय अपने पिछले आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है और इस तरह की शक्ति का उपयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, काफी बल है; लेकिन मैं इस विवाद को गुण-दोष के आधार पर देखने का प्रस्ताव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने विद्वान वकील की पहली दलील को लिया है, जिसके आधार पर याचिका की अनुमति दी जा रही है।

³ 1964 पी.एल.आर. 278;

⁴ 1968 पी.एल.जे. 19

- 7) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूँ और कलेक्टर के 21 सितंबर, 1962 और आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के क्रमशः 5 फरवरी, 1964 और 29 मार्च, 1965 के आक्षेपित आदेशों को रद्द करता हूँ। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.एम.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक, हरियाणा।